सुरंग हादसा : शर्म को...

पेज एक का शेष

बजाए एक महीने में मजदूरों को निकालने का बयान देने लगे तो हाथों में छेनी हथौड़ी और फावड़े लिये मजदूर काम आए। 12 सदस्यों वाली रैट माइनर्स की टोली के सदस्य दो-दो कर बारी-बारी से पाइपों के अंदर घुसे, एक आदमी के आने लायक छेद बनाया और आखिकार फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रैट माइनर्स की इस टोली में फिरोज कुरैशी, मुन्ना कुरैशी, राशिद, इरशाद, अंकुर, जतिन, नसीम, सौरभ, नसीर, वकील हसन और देवेन्द्र शामिल थे। मजदूरों तक सबसे पहले मुन्ना कुरैशी पहुंचा।

इस टोली में ज्यादातर मुस्लिम युवक शामिल थे। यह बात जोर देकर इसलिए याद दिलानी पड़ रही है कि सिलक्यारा सुरंग से कुछ ही किमी दूर उत्तरकाशी का पुरोला है, जहां कुछ महीने पहले मुस्लिम मुक्त उत्तरकाशी और मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड की मुहिम चलाई गई थी और इस क्षेत्र में रह रहे मुसलमानों को रातों-रात इस इलाके को छोड़ना पड़ा था।

सुरंग से बेशक सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया हो, लेकिन यह हादसा कई सवाल छोड़ गया है। पहला सवाल यह कि सुरंग में सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे। जबकि इस तरह की सुरंग बनाने के दौरान एक ह्यूम पाइप लगाई जाती है, ताकि ऐसा हादसा हो तो वहां काम कर रहे लोग बाहर आ सकें। इसके अलावा इस तरह के निर्माणों से पहले जियोलॉजिकल और जियोटेक्निक जांच होती है, वह हुई या नहीं, हुई तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह कि उत्तराखंड जैसे आपदा वाले प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र इतना ढीला क्यों है कि सुरंग के भीतर 60 मीटर मलबा हटाने में 17 दिन लगे एक और सबसे बड़ा सवाल यह कि सुरंग बनाने वाली कंपनी पर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मजदूरों को एक-एक लाख रुपये उत्तराखंड सरकार ने दिये, जब यह राशि कंपनी से दिलवाई जानी चाहिए थी। कंपनी किसकी है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। समाचारों में यह बात सामने आई थी कि नवयुग इंजीनिरिंग नाम की इस कंपनी को कुछ समय पहले अडानी ने खरीद लिया था। अडानी ग्रुप की ओर से इस पर कोई सफाई अब तक नहीं दी गई है।

बड़ी-बड़ी मशीनों और आस्ट्रेलियन एक्सपर्ट के फेल हो जाने के बाद रैट माइनर्स ने जब फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया तो फिर से नाटकबाजी शुरू की गई। समझा जाता है कि सुरंग से निकालने के कई घंटे बाद उनको निकाले जाने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जब उन्हें कैमरे पर लाया गया तो नहाए-धोए और नये कपड़े पहने हुए थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ तो मुख्यमंत्री और वहां मौजूद केन्द्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के पैर छूते भी नजर आये। बताया यह गया कि वे अभी-अभी सुरंग से निकलकर आये हैं। जानकारों को कहना है कि 17 दिन तक हुई किरकिरी से बचने और कोई सुरंगों पर सवाल न उठाये इसलिए इस तरह की नाटकबाजी की गई और एक जानलेवा लापरवाही का सामान्यीकरण करने का प्रयास किया गया।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

Paytm
MM
Majdoor Morcha
UPI ID: 8851091460@paytm
8851091460
Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग हादसा :केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं है आपदा प्रबंधन की विशेषज्ञता

प्रदीप सिंह

नई दिल्ली। सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग में 41 मजदूरों के फंसने और फिर 17 दिन की अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की दर्जनों एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बाद मजदूरों के बाहर निकालने की 'असफल' कवायद ने एक साथ भारतीय शासन, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की विशेषज्ञता और तैयारी को बेपर्दा कर दिया। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में लगी तमाम सरकारी एजेंसियां तकनीकी रूप से अक्षम साबित हुईं, वहीं इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि उत्तराखंड जैसे जटिल भौगोलिक और पारिस्थितिकी तंत्र वाले राज्य में भी सरकार हर काम चलताऊ तरीके से कर रही है। उसे न तो पर्यावरण की रक्षा की चिंता है और न ही श्रम कानूनों का ध्यान है।

गौरतलब है कि 17 दिनों तक राज्य और केंद्र की एक दर्जन एजेंसियां, असंख्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक ही पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। 400 घंटों की कड़ी कवायद के बाद उत्तरकाशी सुरंग से 41 लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन इसका श्रेय झांसी से आए देशी पद्धति के कारीगरों- 'रैट होल माइनर्स' को जाता है। जिन्होंने अति आधुनिक मशीनों के फेल होने के बाद छीनी-हथौड़ी से मलबे को खोदकर मात्र 26 घंटों में मजदूरों को बाहर निकालने को साकार कर दिया।

17 दिनों तक चले बचाव अभियान में कम से कम 652 सरकारी कर्मचारी तैनात किए गए थे। इनमें पुलिस विभाग से 189, स्वास्थ्य विभाग से 106, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से 77, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से 62, राज्य आपदा मोचन बल से 39, जल संस्थान उत्तरकाशी से 46, विद्युत विभाग से 32 और सीमा सड़क संगठन से 38 अधिकारी, कर्मचारी और विशेषज्ञ शामिल थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के विशेष अधिकारी भास्कर खुल्बे के अनुसार, यदि इसमें स्वतंत्र श्रमिकों और निजी कंपनी के कर्मचारियों को शामिल किया जाए, तो ऑपरेशन में योगदान देने वालों की संख्या 1,000 को पार कर जाएगी।

चारधाम परियोजना में पर्यावरण और श्रम कानूनों का उल्लंघन

उत्तराखंड में ताबड़तोड़ विकास परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन चारधाम परियोजना ने तीर्थयात्रा मार्ग बनाने के नाम पर पहाड़ की पारिस्थितिकी तंत्र को तहस-नहस कर दिया है। निर्माणाधीन सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग की दुर्घटना पहाड़ों में मानव निर्मित आपदाओं की सृजित कहानियों में से एक है। जो देश के सामने आ गयी है। लेकिन विकास के नाम पर वहां चल रहे कॉर्पोरेट लूट ने पूरे हिमालय अंचल को खतरनाक जोन में पहुंचा दिया है।

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह केवल इस तथ्य के कारण नहीं है कि चार प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल यहां स्थित हैं, बल्कि इस वास्तविकता के कारण भी है कि यहां निवास करने वाली विभिन्न जातियों-समुदायों ने पूरे हिमालयी परिदृश्य को पवित्र माना है, उनका दृढ़ विश्वास है कि युवा और नाजुक हिमालयी पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने से न केवल पर्वतवासियों के लिए, बल्कि समूचे मानव जाति के लिए विनाशकारी हो सकता है। हिमालय एक ऐसे भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है जहां माना जाता है कि जंगलों, चोटियों, अल्पाइन घास के मैदानों, घाटियों और जल क्षेत्रों के माध्यम से पहाड़ के जटिल संरचना की रक्षा होती है। आधुनिक संसाधनों की भूखी "शिक्षित" आबादी के लिए, यह अंध विश्वास हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस विश्वास प्रणाली से ही आज तक हिमालय क्षेत्र की रक्षा होती रही है, जिसे अब विकास धीरे-धीरे निगल रहा है।

2013 में केदारनाथ बाढ़, जोशीमठ में घरों और होटलों के साथ-साथ नरसिंह मंदिर में दरारें आदि पहाड़ के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और बेतरतीब निर्माण के कारण ही सामने आई हैं। हालांकि, आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोग उत्तराखंड के चार धाम को राष्ट्रीय स्तर पर वोट पाने में मददगार मान रहे हैं और पहाड़ को कॉर्पोरेट के लिए दूध देने वाली गाय के रूप में देखते हैं, पहाड़ के लोग नई दिल्ली में अपने भाग्य निर्माताओं से अधिक सहानुभूति और समझ की अपेक्षा करते हैं, जो इस क्षेत्र में हर आपदा के लिए किसी न किसी रूप में जिम्मेवार हैं।

हिमालयी समुदायों को पता है कि उत्तराखंड अब देश की बहु-लेन राजमार्गों, रेल नेटवर्क, हेलीपैड और चार धाम यात्रा के लिए बनने वाला राजमार्ग उनके ऊपर थोपा गया विकास है, जो सदियों के पारिस्थितिक संतुलन को छिन्न-भिन्न कर स्थानीय समुदायों को आने वाली सदियों तक आपदा के अंधी सुरंग में डाल दिया है।

दीपावली के दिन भी चल रहा था सुरंग निर्माण का कार्य

होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश भर में अवकाश होता है। इस दिन सरकारी, गैर सरकारी और घरेलू काम को बंद कर लोग त्योहार मनाते हैं। लेकिन नए भारत में 41 मजदूरों से सुरंग के अंदर काम लिया जा रहा था। यह सरासर अमानवीय और श्रम कानूनों का उल्लंघन है। आश्चर्य की बात यह है कि श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने में भारत सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ही लगा हुआ है।

केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं है आपदा प्रबंधन की विशेषज्ञता

12 नवंबर को सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग धसने और उसमें 41 मजदूरों के फंसने के बाद से ही बचाव के लिए कई देशी-विदेशी एजेंसियों को वहां लगाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल से लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा हर छोटे या बड़े विकास पर नज़र रख रहे थे।

इनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड, नवयुग, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, टेहरी हाइड्रो विकास निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग वर्क्स, केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ सेना और वायु सेना के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल थे। फिर अनगिनत अनाम नायक थे- पुलिसकर्मी जो चौबीसों घंटे पहरा देते थे; बचावकर्मियों के लिए नियमित भोजन तैयार करने वाले रसोइये; ड्राइवर जिन्होंने पर उपकरण पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम किया।

बचावकर्मी फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक साथ पांच योजनाओं पर काम कर रहे थे। प्रत्येक को अलग-अलग एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जिनमें अलग-अलग कौशल और रणनीति के विशेषज्ञ शामिल थे। लेकिन हर विशेषज्ञ की रणनीति फ्लॉप साबित हुई। और अंत में रैट होल माइनर्स (जो देश में कानूनन प्रतिबंधित है) को लगाया गया, और तब जाकर सफलता मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश की तमाम एजेंसियां और आपदा प्रबंधन विभाग सिर्फ हाथी के दांत हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं?

(प्रदीप सिंह जनचौक के राजनीतिक संपादक हैं।)